



Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam

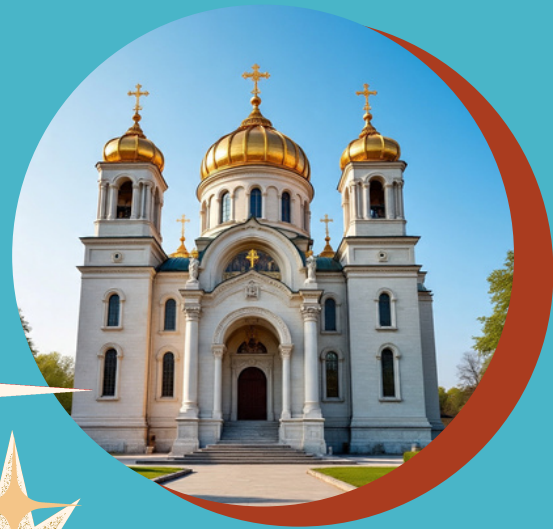


BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

7 - 13 DEC 2025

2ND WEEK OF NOVEMBER

50+ MCQ
with detailed
explanation



- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



**Ques: What is the main objective of the MoU signed between SBI and BOI?
SBI और BOI के बीच किए गए MoU का मुख्य उद्देश्य क्या है?**

- A) Launching new retail banking services / नई रिटेल बैंकिंग सेवाएँ शुरू करना
- B) Establishing a Centre of Excellence in Strategic Partnership / रणनीतिक साझेदारी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना
- C) Merging both banks / दोनों बैंकों का विलय
- D) Expanding international branches / अंतरराष्ट्रीय शाखाओं का विस्तार
- E) Offering microfinance to rural areas / ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस प्रदान करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) and Bank of India (BOI) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to jointly establish a Centre of Excellence (CoE) in Strategic Partnership.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने रणनीतिक साझेदारी में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
- The initiative aims to strengthen leadership and expertise in project financing across India.
- इस पहल का उद्देश्य भारत भर में परियोजना वित्तपोषण में नेतृत्व और विशेषज्ञता को सुदृढ़ करना है।
- Key areas of focus include joint financing for big projects, enhanced brand presence, and employee training and development.
- मुख्य फोकस क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए संयुक्त वित्तपोषण, ब्रांड की उपस्थिति को बढ़ाना और कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास शामिल हैं।

About State Bank of India (SBI):

- Established : 01 July 1955
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- Chairman : Challa Sreenivasulu Setty

About Bank of India:

- Established : 1906
- HQ : Mumbai

- MD & CEO : Rajneesh Karnatak
- Tagline : Relationship Beyond Banking

Ques: Which Indian state received the highest share of FDI Equity inflow in the first half of FY 2025-26?

FY 2025-26 की पहली छमाही में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त किया?

- A) Karnataka / कर्नाटक
- B) Gujarat / गुजरात
- C) Tamil Nadu / तमिल नाडु
- D) Maharashtra / महाराष्ट्र
- E) Telangana / तेलंगाना

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- India's FDI inflow surged 18% to \$35.18 billion during April–September 2025-26, with the U.S. showing the sharpest rise among major contributors.
 - भारत का एफडीआई प्रवाह अप्रैल–सितंबर 2025-26 में 18% बढ़कर \$35.18 बिलियन हो गया, जिसमें अमेरिका प्रमुख देशों में सबसे तेज वृद्धि दिखा।
 - The services sector, particularly financial and business services, attracted the highest share of FDI.
 - सेवा क्षेत्र, विशेषकर वित्तीय और व्यापार सेवाओं, ने सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित किया।
 - Top investing countries included Singapore, Mauritius, and the U.S.A.
 - शीर्ष निवेशक देशों में सिंगापुर, मॉरीशस और अमेरिका शामिल हैं।
 - Maharashtra received the highest FDI share at 31% (\$10,571 million), followed by Karnataka (21%) and Gujarat (15%).
 - महाराष्ट्र ने 31% के साथ सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया कुल)\$10,571 मिलियन(, इसके बाद कर्नाटक)21%) और गुजरात)15%) रहे।
-

Ques: How much amount is the government expected to raise by selling its 6% stake in Bank of Maharashtra?

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी 6% हिस्सेदारी बेचकर सरकार कितनी राशि जुटाने की उम्मीद कर रही है?

- A) ₹1,850 crore
- B) ₹2,000 crore
- C) ₹2,492 crore
- D) ₹3,100 crore
- E) ₹4,250 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The government diluted a 6% stake in Bank of Maharashtra (BoM) through an Offer-for-Sale (OFS), with a floor price of ₹54 per share.
- सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) में अपनी 6% हिस्सेदारी ऑफर) सेल-फॉर-OFS) के माध्यम से बेची, जिसका फ्लोर प्राइस ₹54 प्रति शेयर था।
- The stake sale is expected to raise around ₹2,492 crore for the government.
- इस हिस्सेदारी बिक्री से सरकार लगभग ₹2,492 करोड़ जुटाने की उम्मीद कर रही है।
- After share allotment, BoM will comply with SEBI's Minimum Public Shareholding (MPS) norms.
- शेयर आवंटन के बाद BoM SEBI के न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (MPS) मानदंडों का पालन करेगा।
- Prior to the OFS, the government held a 79.60% stake in BoM.
- OFS से पहले सरकार की BoM में हिस्सेदारी 79.60% थी।
- Bank of Maharashtra is headquartered in Pune, Maharashtra.
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है।
- The oversubscribed OFS helped the government raise funds while also supporting BoM in meeting regulatory public shareholding requirements.
- अधिक मांग वाली OFS ने सरकार को फंड जुटाने में मदद की और साथ ही BoM को नियामक न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी मानदंडों को पूरा करने में भी सहायता दी।

Ques: What recent initiative has Tamilnad Mercantile Bank (TMB) launched to improve loan processing?

तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक (TMB) ने ऋण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में कौन सा नया कदम उठाया है?

- A) Digital Savings Account Platform / डिजिटल सेविंग्स अकाउंट प्लेटफॉर्म
- B) Loan Origination System (LOS) / लोन ऑरिजिनेशन सिस्टम (LOS)
- C) Mobile Wallet App / मोबाइल वॉलेट ऐप
- D) Investment Advisory Portal / निवेश परामर्श पोर्टल
- E) Blockchain-based Payment System / ब्लॉकचेनप्रणाली भुगतान आधारित-

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Tamilnad Mercantile Bank (TMB) has launched a new Loan Origination System (LOS) developed with Nucleus Software to streamline loan processing.
- तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक (TMB) ने Nucleus Software के साथ मिलकर ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए नया लोन ऑरिजिनेशन सिस्टम (LOS) लॉन्च किया है।
- The system aims for faster, standardized, and more accurate loan processing with automated checks and digital workflows.
- यह सिस्टम तेज़, मानकीकृत और अधिक सटीक ऋण प्रक्रिया के लिए ऑटोमेटेड चेक और डिजिटल वर्कफ्लो के साथ तैयार किया गया है।
- Uniform appraisal mechanism is included to ensure consistent credit decisions and improved customer experience.
- इसमें एक समान मूल्यांकन तंत्र शामिल है ताकि लगातार बेहतर क्रेडिट निर्णय लिए जा सकें और ग्राहक अनुभव में सुधार हो।
- The new system is expected to reduce Turn Around Time (TAT) for loan approvals.
- नए सिस्टम से ऋण अनुमोदन के टर्नअराउंड टाइम (TAT) में कमी आने की उम्मीद है।

Ques: Which projects did the Asian Development Bank (ADB) approve loans for in Assam and Meghalaya?

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने असम और मेघालय में किन परियोजनाओं के लिए ऋण को मंजूरी दी?

- A) Assam – Infrastructure, Meghalaya – Renewable Energy / असम – अवसंरचना,

मेघालय – नवीकरणीय ऊर्जा

B) Assam – Healthcare & Medical Education, Meghalaya – Ecotourism / असम – स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा, मेघालय – इकोटूरिज़्म

C) Assam – Agriculture, Meghalaya – Water Supply / असम – कृषि, मेघालय – जल आपूर्ति

D) Assam – Transport, Meghalaya – Education / असम – परिवहन, मेघालय – शिक्षा

E) Assam – Industrial Development, Meghalaya – Mining / असम – औद्योगिक विकास, मेघालय – खनन

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) approved USD 398.8 million for healthcare transformation and medical education projects in Assam.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने असम में स्वास्थ्य देखभाल सुधार और चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के लिए 398.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए।
- A separate loan of USD 77 million was approved for the Ecotourism project in Meghalaya.
- मेघालय में इकोटूरिज़्म परियोजना के लिए अलग से 77 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया गया।
- The loans aim to improve healthcare infrastructure in Assam and promote sustainable tourism in Meghalaya.
- इन ऋणों का उद्देश्य असम में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में सुधार करना और मेघालय में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है।

About Asian Development Bank :

- Established : 19 December 1966
 - HQ : Manila, Philippines
 - Members : 69
 - Chief Economist : Albert Park
 - President : Masato Kanda
-

Ques: What is the significance of Indian banks achieving ISO 20022 readiness?

भारतीय बैंकों द्वारा ISO 20022 मानक की तैयारी पूरी करने का महत्व क्या है?

- A) To expand domestic ATM networks / घरेलू एटीएम नेटवर्क का विस्तार करना
- B) To enable richer, structured, and detailed payment data for cross-border transactions / सीमासमृद्ध लिए के लेनदेन पार-, संरचित और विस्तृत भुगतान डेटा सक्षम करना
- C) To reduce interest rates on loans / ऋण पर ब्याज दरें कम करना
- D) To merge all public sector banks / सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करना
- E) To launch a new digital currency / नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Indian banks have fully implemented SWIFT's ISO 20022 messaging standard ahead of the 22 November 2025 deadline.
- भारतीय बैंकों ने 22 नवंबर 2025 की समय सीमा से पहले SWIFT के ISO 20022 मैसेजिंग मानक को पूरी तरह लागू कर लिया है।
- With 100% readiness, India has outperformed the global compliance average of 87%.
- 100% तैयारियों के साथ, भारत ने वैश्विक अनुपालन औसत 87% को पीछे छोड़ दिया है।
- ISO 20022 enables richer, structured, and detailed payment data, improving analytics, compliance, and fraud-prevention capabilities.
- ISO 20022 समृद्ध, संरचित और विस्तृत भुगतान डेटा सक्षम करता है, जो विश्लेषण, अनुपालन और धोखाधड़ी है। बनाता बेहतर को क्षमताओं रोकथाम-
- The transition began in March 2023, with a coexistence period allowing exchange of both MT and ISO 20022 messages; after 22 November 2025, ISO 20022 becomes mandatory for all cross-border payments.
- मार्च 2023 में संक्रमण शुरू हुआ, जिसमें MT और ISO 20022 संदेशों का आदान प्रदान-थी गई रखी अवधि अस्तित्व-सह लिए के करने; 22 नवंबर 2025 के बाद सभी सीमा पार-लिए के भुगतान ISO 20022 अनिवार्य हो जाएगा।
- Non-compliant banks may face severe payment disruptions and penalties.
- जो बैंक इस मानक का पालन नहीं करेंगे, उन्हें गंभीर भुगतान व्यवधान और संभावित दंड का सामना करना पड़ सकता है।

Ques: NPCI International Payments partnered with ACLEDA Bank of which country to enable UPI acceptance?

NPCI International Payments ने किस देश के ACLEDA Bank के साथ साझेदारी की है ताकि UPI वहाँ स्वीकार किया जा सके?

- A) Thailand / थाईलैंड
- B) Vietnam / वियतनाम
- C) Cambodia / कंबोडिया
- D) Singapore / सिंगापुर
- E) Malaysia / मलेशिया

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- NPCI International Payments (NIPL) has partnered with Cambodia-based ACLEDA Bank to enable acceptance of India's real-time digital payment system UPI in Cambodia.
 - NPCI International Payments (NIPL) ने कंबोडिया के ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि कंबोडिया में भारत का रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान सिस्टम UPI स्वीकार किया जा सके।
 - The partnership will also allow India to accept Cambodia's national QR network Bakong (KHQR), facilitating cross-border payments.
 - यह साझेदारी भारत में कंबोडिया के राष्ट्रीय QR नेटवर्क Bakong (KHQR) को स्वीकार करने की सुविधा भी प्रदान करेगी, जिससे सीमा पार भुगतान आसान होंगे।
 - Indians and Cambodians will be able to pay via QR codes at tourist spots, restaurants, and retail outlets in both countries, promoting seamless and faster cross-border transactions.
 - भारतीय और कंबोडियाई नागरिक दोनों देशों में पर्यटन स्थलों, रेस्टोरेंट्स और रिटेल दुकानों पर QR कोड के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे, जिससे सीमा पार लेनदेन आसान और तेज़ होंगे।
-

Ques: By what percentage did consumer grievances under the RBI's Ombudsman framework increase in FY25 compared to FY24?

आरबीआई के लोकपाल ढांचे के तहत उपभोक्ता शिकायतों में FY24 की तुलना में FY25 में

कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- A) 10.25%
- B) 11.80%
- C) 17.40%
- D) 15.20%
- E) 13.55%

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Consumer grievances under the Reserve Bank of India's ombudsman framework saw a notable rise in FY25, indicating growing dissatisfaction with banking and financial services.
- आरबीआई के लोकपाल ढांचे के तहत उपभोक्ता शिकायतों में FY25 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से बढ़ती असंतुष्टि को दर्शाती है।
- Under the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, complaints increased to 13,34,244 in FY25 from 11,75,075 in FY24, marking a 13.55% rise.
- Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme के तहत शिकायतें FY24 के 11,75,075 से बढ़कर FY25 में 13,34,244 हो गईं, यानी 13.55% की वृद्धि।
- Of the total complaints, the 24 RBI Ombudsman Offices received 2,96,321, while the Centralised Receipt and Processing Centre (CRPC) handled 9,11,384 cases and forwarded many to ombudsman offices and Consumer Education and Protection Cells (CEPCs).
- कुल शिकायतों में से 24 आरबीआई लोकपाल कार्यालयों को 2,96,321 शिकायतें मिलीं, जबकि CRPC ने 9,11,384 मामलों को संसाधित किया और कई को लोकपाल कार्यालयों व CEPC को भेजा।
- Over 7.7 lakh cases were marked as non-maintainable and closed at the CRPC level.
- 7.7 लाख से अधिक मामलों को गैर-उपयुक्त मानकर CRPC स्तर पर बंद कर दिया गया।
- Complaints against banks were the highest at 2.41 lakh (81.53%), followed by NBFCs with 43.8K cases (14.80%).
- बैंकों के खिलाफ शिकायतें सबसे अधिक 2.41 लाख (81.53%) रहीं, इसके बाद NBFCs की 43.8K (14.80%) शिकायतें रहीं।
- Complaints against private sector banks rose from 34.39% to 37.53%, while those against public sector banks declined from 38.32% to 34.80%.
- निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायतें 34.39% से बढ़कर 37.53% हो गईं, जबकि

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शिकायतें 38.32% से घटकर 34.80% रह गईं।

- Loans and advances accounted for the highest complaints at 29.25%, followed by credit cards (17.15%), mobile/electronic banking (16.86%), and deposit account opening (16.84%).
- ऋण और अग्रिम से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक 29.25% रहीं, इसके बाद क्रेडिट कार्ड (17.15%), मोबाइल/ई-बैंकिंग (16.86%) और जमा खाता खोलने (16.84%) से संबंधित शिकायतें रहीं।
- Metro cities recorded the most complaints at 45.86%, followed by urban (25.64%), semi-urban (18.46%), and rural areas (10.04%).
- मेट्रो शहरों में सबसे अधिक 45.86% शिकायतें दर्ज हुईं, इसके बाद शहरी (25.64%), अर्ध-शहरी (18.46%) और ग्रामीण क्षेत्रों (10.04%) में शिकायतें दर्ज हुईं।
- The complaint disposal rate fell from 95.10% in FY24 to 93.07% in FY25.
- शिकायत निस्तारण दर FY24 के 95.10% से घटकर FY25 में 93.07% हो गई।

Ques: What was the year-on-year (YoY) growth of bank credit in India as of 14 November 2025?

14 नवंबर 2025 तक भारत में बैंक क्रेडिट की वर्ष) वर्ष-दर-YoY) वृद्धि कितनी रही?

- A) 9.5%
- B) 10.2%
- C) 11.4%
- D) 11.5%
- E) 12.0%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- As of 14 November 2025, India's bank credit growth on a year-on-year (YoY) basis stood at 11.4%.
- 14 नवंबर 2025 तक भारत में बैंक क्रेडिट की वर्ष) वर्ष-दर-YoY) वृद्धि 11.4% रही।
- Deposit growth during the same period rose to 10.2% from 9.5% two weeks earlier, indicating healthy liquidity in the system.
- इसी अवधि में जमाओं की वृद्धि 9.5% से बढ़कर 10.2% हो गई, जो प्रणाली में स्वस्थ तरलता को दर्शाती है।
- Gold loans continued their triple-digit surge, up 129% YoY to Rs 41,409 crore

as of 31 October 2025.

- सोने के ऋण में लगातार तीन अंकों की वृद्धि हुई, जो 31 अक्टूबर 2025 तक 129% YoY बढ़कर ₹41,409 करोड़ हो गया।
- Consumer durable loans grew only 1% to Rs 23,646 crore, reflecting a weak festive demand compared to 6.9% growth last year.
- उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के ऋण में केवल 1% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की 6.9% वृद्धि की तुलना में त्योहारों के कमजोर प्रभाव को दर्शाता है।
- Outstanding bank credit as of 14 November 2025 was Rs 194 lakh crore, while outstanding deposits stood at Rs 241 lakh crore.
- 14 नवंबर 2025 तक बकाया बैंक क्रेडिट ₹194 लाख करोड़ और बकाया जमा ₹241 लाख करोड़ था।

Ques: Under RBI's new metal loan norms, loans will NOT be provided against which of the following?

आरबीआई के नए मेटल लोन नियमों के तहत किस वस्तु पर लोन नहीं दिया जाएगा?

- A) Gold Jewellery / सोने के आभूषण
- B) Silver Coins / चांदी के सिक्के
- C) Bullion (Gold/Silver Bars) / बुलियन (सोना/चांदी बार)
- D) Silver Jewellery / चांदी के आभूषण
- E) Gold Coins / सोने के सिक्के

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI has liberalized metal loan rules, allowing banks and NBFCs to provide loans against gold and silver jewellery or coins.
- आरबीआई ने मेटल लोन नियमों को उदार बनाते हुए बैंकों और NBFCs को सोने और चांदी के आभूषण या सिक्कों के बदले लोन देने की अनुमति दी है।
- The new norms will come into effect from April 1, 2026, and apply to commercial banks, SFBs, RRBs, UCBs, cooperative banks, NBFCs, and HFCs.
- नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और ये वाणिज्यिक बैंक, SFBs, RRBs, UCBs, सहकारी बैंक, NBFCs और HFCs पर लागू होंगे।
- Loans can be given only against gold/silver jewellery or coins; loans against

bullion (gold/silver bars), ETFs, or mutual fund units are not allowed.

- लोन केवल सोने/चांदी के आभूषण या सिक्कों पर ही दिया जाएगा; बुलियन (सोना/चांदी बार), ETFs या MF units पर लोन की अनुमति नहीं है।
- RBI has specified pledging limits: Gold jewellery—1 kg, Silver jewellery—10 kg, Gold coins—50 g, Silver coins—500 g.
- RBI ने पेंडिंग लिमिट तय की हैं: सोने के आभूषण—1 किलो, चांदी के आभूषण—10 किलो, सोने के सिक्के—50 ग्राम, चांदी के सिक्के—500 ग्राम।
- The move aims to streamline lending, enhance transparency, and strengthen risk management.
- यह कदम लेंडिंग को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

Ques: Which state received USD 109.97 million under the Skills Development Programme?

कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 109.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस राज्य को प्राप्त हुए?

- A) Gujarat / गुजरात
- B) Punjab / पंजाब
- C) Haryana / हरियाणा
- D) Odisha / ओडिशा
- E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Maharashtra received USD 500 million for the Power Distribution Enhancement Programme, aimed at modernising rural power infrastructure and supplying daytime solar electricity to farmers.
- महाराष्ट्र को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पावर डिस्ट्रीब्यूशन एन्हांसमेंट प्रोग्राम के लिए मिली, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का आधुनिकीकरण और किसानों को दिन के समय सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है।
- Madhya Pradesh received USD 190.6 million for the Indore Metro Rail Project, supporting an 8.62 km underground metro line with 7 stations, improving connectivity to Indore Airport.

- मध्य प्रदेश को 190.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए मिली, जो 8.62 किमी भूमिगत मेट्रो लाइन और 7 स्टेशनों के निर्माण के लिए है, जिससे इंदौर हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
- Gujarat received USD 109.97 million under the Skills Development Programme, to upgrade 11 mega ITIs, establish centres of excellence, and train youth in high-growth sectors.
- गुजरात को 109.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुए, जिसका उद्देश्य 11 मेगा आईटीआई का उन्नयन, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और युवाओं को उच्च-विकास क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना है।

Ques: LIC has recently signed a bancassurance pact with which bank to expand customer access to life insurance products?

LIC ने हाल ही में किस बैंक के साथ बैंकएश्योरेंस समझौता किया है ताकि ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों तक पहुँच बढ़ाई जा सके?

- A) Yes Bank / यस बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- LIC has entered into a strategic bancassurance partnership with Yes Bank to provide its life insurance products to customers through both branches and digital platforms.
- LIC ने Yes Bank के साथ एक रणनीतिक बैंकएश्योरेंस साझेदारी की है ताकि ग्राहक शाखाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से LIC के जीवन बीमा उत्पादों तक पहुँच सकें।
- The partnership leverages LIC's network of over 3,600 branches and satellite offices, combined with Yes Bank's branch network.
- यह साझेदारी LIC की 3,600 से अधिक शाखाओं और सैटेलाइट कार्यालयों और Yes Bank के नेटवर्क की संयुक्त ताकत का उपयोग करेगी।
- The agreement aims to increase insurance penetration and expand customer

reach across India.

- यह समझौता बीमा कवरेज बढ़ाने और भारत में ग्राहक पहुँच का विस्तार करने का लक्ष्य रखता है।
- Customers can now access LIC's life insurance offerings seamlessly through Yes Bank's physical and digital channels.
- अब ग्राहक Yes Bank के भौतिक और डिजिटल चैनलों के माध्यम से LIC के जीवन बीमा उत्पादों तक सहज पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

Ques: How many Aadhaar authentication transactions were executed in November 2025?

नवंबर 2025 में कितनी आधार प्रमाणीकरण लेन-देन की गईं?

- A) 219 crore
- B) 231 crore
- C) 250 crore
- D) 200 crore
- E) 245 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Aadhaar number holders executed 231 crore authentication transactions in November 2025, showing a growth of almost 8.5% compared to November 2024.
- नवंबर 2025 में आधार धारकों ने 231 करोड़ प्रमाणीकरण लेन-देन किए, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8.5% की वृद्धि दर्शाता है।
- In October 2025, 219.51 crore transactions were recorded, showing month-on-month growth.
- अक्टूबर 2025 में 219.51 करोड़ लेन-देन दर्ज हुए, जिससे महीने-दर-महीने वृद्धि स्पष्ट होती है।
- Nearly 60% of Digital Life Certificates generated by pensioners used Aadhaar face authentication; overall, 28.29 crore face authentication transactions were done in November 2025, up from 12.04 crore in Nov 2024.
- लगभग 60% डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनभोगियों द्वारा आधार फेस प्रमाणीकरण का

उपयोग कर उत्पन्न किए गए; कुल 28.29 करोड़ फेस प्रमाणीकरण लेन-देन नवंबर 2025 में हुए, जबकि नवंबर 2024 में 12.04 करोड़ थे।

- e-KYC transactions also rose significantly to 47.19 crore in November 2025, a more than 24% increase from November 2024.
- e-KYC लेन-देन भी नवंबर 2025 में 47.19 करोड़ तक बढ़ गए, जो नवंबर 2024 की तुलना में 24% से अधिक की वृद्धि है।

Ques: As per the fiscal data for April–October 2025, India’s fiscal deficit stood at what level?

अप्रैल–अक्तूबर 2025 के वित्तीय आँकड़ों के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा किस स्तर पर रहा?

- A) ₹6 lakh crore
- B) ₹7.2 lakh crore
- C) ₹8.25 lakh crore
- D) ₹9.5 lakh crore
- E) ₹10 lakh crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- In April–October 2025, India’s fiscal deficit reached ₹8.25 lakh crore, which is 52.6% of the FY26 target.
- अप्रैल–अक्तूबर 2025 में भारत का राजकोषीय घाटा ₹8.25 लाख करोड़ रहा, जो FY26 लक्ष्य का 52.6% है।
- Net tax receipts stood at ₹12.74 lakh crore, slightly lower than ₹13.05 lakh crore in the same period of 2024.
- शुद्ध कर प्राप्तियाँ ₹12.74 लाख करोड़ रहीं, जो 2024 की समान अवधि के ₹13.05 लाख करोड़ से थोड़ी कम हैं।
- Non-tax revenue increased to ₹4.89 lakh crore, compared to ₹4 lakh crore last year.
- गैर-कर राजस्व बढ़कर ₹4.89 लाख करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹4 लाख करोड़ था।
- Total expenditure rose to ₹26.26 lakh crore, up from ₹24.7 lakh crore in the previous year.

- कुल व्यय बढ़कर ₹26.26 लाख करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹24.7 लाख करोड़ था।
- Capital expenditure (Capex) sharply increased to ₹6.18 lakh crore, compared to ₹4.7 lakh crore in April–October 2024.
- पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़कर ₹6.18 लाख करोड़ हो गया, जो अप्रैल–अक्तूबर 2024 के ₹4.7 लाख करोड़ से काफी अधिक है।
- Fiscal stance remains focused on infrastructure-led growth.
- सरकार का वित्तीय फोकस अवसंरचना-प्रधान विकास पर बना हुआ है।
- Concern remains over revenue shortfall amid rising expenditure.
- बढ़ते व्यय के बीच राजस्व की कमी चिंता का विषय बनी हुई है।

Ques: ESAF Small Finance Bank recently received an upgraded ESG rating. What is its new ESG score as per CareEdge Ratings?

ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को हाल ही में CareEdge द्वारा उन्नत ESG रेटिंग मिली। नया ESG स्कोर क्या है?

- A) 62.3
- B) 68.1
- C) 71.9
- D) 75.4
- E) 82.6

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- ESAF Small Finance Bank received one of the highest ESG ratings in Indian banking.
- ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे उच्च ESG रेटिंग्स में से एक प्राप्त हुई।
- CareEdge ESG Ratings upgraded its score to 75.4, placing the bank in the CareEdge-ESG 1 category.
- CareEdge ESG Ratings ने बैंक का स्कोर बढ़ाकर 75.4 कर दिया, जिससे यह CareEdge-ESG 1 श्रेणी में शामिल हो गया।
- The previous year's ESG score was 68.1, showing a significant improvement.
- पिछले वर्ष का स्कोर 68.1 था, जो महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है।
- ESAF SFB demonstrated strong performance across Environmental, Social,

and Governance parameters with best-in-class disclosures.

- पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों ही मापदंडों पर ESAF SFB ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और इसके खुलासे भी सर्वोत्तम श्रेणी के हैं।
- The Social pillar score was 82.6, well above the industry median.
- सामाजिक स्तंभ का स्कोर 82.6 रहा, जो उद्योग के औसत से काफी अधिक है।
- Key strengths include community development programmes, priority-sector lending, and a women-centric financial inclusion model.
- प्रमुख ताकतों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्राथमिक क्षेत्र ऋण और महिला केंद्रित-हैं। शामिल मॉडल समावेशन वित्तीय
- With a score of 75.4, ESAF SFB ranks among the top-performing institutions under the SEBI ESG framework.
- 75.4 के स्कोर के साथ, ESAF SFB SEBI ESG ढांचे के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं में शामिल है।

Ques: As per NABARD, agricultural credit from banks is expected to reach what level in FY26?

NABARD के अनुसार, FY26 में बैंकों से कृषि ऋण किस स्तर तक पहुँचने का अनुमान है?

- A) ₹25 lakh crore
- B) ₹28.69 lakh crore
- C) ₹30 lakh crore
- D) ₹32.5 lakh crore
- E) ₹35 lakh crore

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Credit to agriculture from commercial banks and regional rural banks (RRBs) is expected to exceed ₹32.5 lakh crore in FY26, the highest ever, according to NABARD.
- NABARD के अनुसार, FY26 में वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) द्वारा कृषि क्षेत्र को ₹32.5 लाख करोड़ से अधिक ऋण देने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर होगा।
- This growth is driven by rising formalisation of rural lending and increasing credit demand.

- ग्रामीण ऋण के औपचारिककरण और बढ़ती ऋण मांग के कारण यह वृद्धि हो रही है।
- In the first half of FY26, banks have already disbursed ₹14.51 lakh crore in farm loans.
- FY26 की पहली छमाही में ही बैंकों ने ₹14.51 लाख करोड़ कृषि ऋण वितरित कर दिया है।
- FY25 performance: Total agriculture credit was ₹28.69 lakh crore, provided by commercial banks, cooperatives, and RRBs.
- FY25 प्रदर्शन: कुल कृषि ऋण ₹28.69 लाख करोड़ रहा, जिसे वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी संस्थाओं और RRBs ने प्रदान किया।
- Loan share : 60%: short-term crop loans and 40%: investment credit (agriculture + allied sectors)
- ऋण वितरण: 60%: अल्पकालिक फसल ऋण और 40%: निवेश ऋण (कृषि + संबद्ध क्षेत्र)
- Regional disparity: Southern states (AP, Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu) received 48% of agricultural loans in FY25, despite having only 17% of India's gross cropped area.
- क्षेत्रीय असमानता: दक्षिणी राज्यों को FY25 में 48% कृषि ऋण मिला, जबकि उनके पास भारत के सकल बोया क्षेत्र का केवल 17% हिस्सा है।
- NABARD identifies the causes as weak rural financial infrastructure and low financial literacy in many other states.
- NABARD के अनुसार, कई राज्यों में ग्रामीण वित्तीय अवसंरचना कमजोर है और वित्तीय साक्षरता कम होने से यह असमानता बढ़ती है।
- Kisan Credit Cards (KCC) and formal banking channels are expected to help banks achieve the FY26 target of ₹32.5 lakh crore.
- FY26 के ₹32.5 लाख करोड़ लक्ष्य को हासिल करने में KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) और औपचारिक बैंकिंग चैनल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

Ques: Who has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of Bank of America NA in India?

भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Kaku Nakhate / काकु नखाते
- B) Vikram Sahu / विक्रम साहू
- C) Shombi Sharp / शॉम्बी शार्प
- D) Antonio Guterres / एंटोनियो गुटेरेस
- E) Bhupender Yadav / भूपेंद्र यादव

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Vikram Sahu has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of Bank of America NA (BANA) in India for a tenure of three years.
- विक्रम साहू को भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA (BANA) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
- He replaces Kaku Nakhate, who has been elevated to the role of Chair of Bank of America India.
- उन्होंने काकु नखाते का स्थान लिया है, जिन्हें बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के चेयर पद पर पदोन्नत किया गया है।
- Bank of America NA India was established in 1964 and has its headquarters in Mumbai.
- बैंक ऑफ अमेरिका NA इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

Ques: As per Fitch Ratings' Global Economic Outlook (December 2025), what is India's revised GDP growth forecast for FY26?

फिच रेटिंग्स की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक (दिसंबर)2025) रिपोर्ट के अनुसार, FY26 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है?

- A) 6.2%
- B) 6.4%
- C) 6.9%
- D) 7.4%
- E) 7.8%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Fitch Ratings released its "Global Economic Outlook (GEO) – December 2025" report.
- फिच रेटिंग्स ने अपनी "ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक (GEO) – दिसंबर 2025" रिपोर्ट जारी की।

- The agency revised India's GDP growth forecast for FY26 upward to 7.4%, from its earlier estimate of 6.9%.
- एजेंसी ने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को 6.9% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया।
- The report further projects that India's GDP growth will slow to 6.4% in FY27.
- रिपोर्ट के अनुसार FY27 में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर 6.4% होने की उम्मीद है।
- India's growth rate is expected to moderate further to 6.2% in FY28.
- FY28 में यह दर और घटकर 6.2% होने का अनुमान है।

Ques: Why did India's GST collections soften in November 2025?

भारत में नवंबर 2025 में GST संग्रह क्यों धीमा हुआ?

- A) Decline in exports / निर्यात में गिरावट
- B) Rationalisation move reducing GST rates on hundreds of items / सैकड़ों वस्तुओं पर GST दरें घटाने के कारण
- C) Increase in fuel prices / ईंधन की कीमतों में वृद्धि
- D) Delayed tax filings / कर दाखिल करने में देरी
- E) Economic slowdown / आर्थिक मंदी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- India's GST collections in November 2025 softened due to the rationalisation move that reduced indirect tax rates on 375 items, including soaps and small cars.
- भारत में नवंबर 2025 में GST संग्रह धीमा हुआ क्योंकि सरकार ने 375 वस्तुओं (जैसे) टाकर कर स्लैब को दोपर अप्रत्यक्ष कर दरें घ (साबुन और छोटी कारें 5% और 18%) में समेकित किया।
- Gross GST revenue rose only 0.7% year-on-year to ₹1,70,276 crore in November 2025, compared to ₹1.95 lakh crore in October 2025.
- सकल GST राजस्व नवंबर 2025 में मात्र 0.7% की वृद्धि के साथ ₹1,70,276 करोड़ रहा, जबकि अक्टूबर 2025 में यह ₹1.95 लाख करोड़ था।
- The move also introduced a 40% slab for sin and luxury goods while removing the compensation cess.
- इस कदम में पाप और विलासिता वस्तुओं के लिए 40% का नया स्लैब और क्षतिपूर्ति शुल्क

समाप्त किया गया।

GST Collection of Previous Months :

- Oct 2025 : 1,95,936 Crore
- Sep 2025 : 1,87,346 crore
- August 2025 : 1,86,315 Crore
- July 2025 : 1,95,735 Crore
- June 2025 : 1,84,567 Crore

Ques: What was India's current account deficit (CAD) as a percentage of GDP in Q2 FY26?

भारत में चालू खाता घाटा (CAD) Q2 FY26 में GDP के कितने प्रतिशत के रूप में था?

- A) 0.2%
- B) 4.1%
- C) 2.2%
- D) 3.0%
- E) 1.3%

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- As per RBI data, India's current account deficit (CAD) moderated to \$12.3 billion, which is 1.3% of GDP in July–September 2025 (Q2 FY26), compared to \$20.8 billion, or 2.2% of GDP, in the same period last year.
- RBI के आंकड़ों के अनुसार, भारत का चालू खाता घाटा (CAD) जुलाई–सितंबर 2025 (Q2 FY26) में \$12.3 बिलियन यानी GDP का 1.3% रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह \$20.8 बिलियन या GDP का 2.2% था।
- The merchandise trade deficit also narrowed to \$87.4 billion from \$88.5 billion a year earlier.
- वस्तु व्यापार घाटा भी \$88.5 बिलियन से घटकर \$87.4 बिलियन हो गया।
- Non-resident deposits declined from \$6.2 billion to \$2.5 billion.
- गैर निवासी जमा-\$6.2 बिलियन से घटकर \$2.5 बिलियन हो गए।

Ques: What measures has the RBI announced to inject durable liquidity amid rupee depreciation?

रुपये के मूल्य में गिरावट के बीच स्थायी तरलता बढ़ाने के लिए RBI ने कौन से उपाय घोषित किए हैं?

- A) Repo rate hike / रेपो दर बढ़ाना
- B) Open Market Operation purchases & dollar–rupee swaps / ओपन मार्केट ऑपरेशन और डॉलर–रुपये स्वैप
- C) Cash reserve ratio reduction / नकद आरक्षित अनुपात में कटौती
- D) Forex intervention only / केवल विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप
- E) Government bond buyback / सरकारी बांड खरीद

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- RBI announced it will conduct Open Market Operation (OMO) purchases of government securities worth ₹1 trillion and a three-year dollar–rupee buy/sell swap of \$5 billion to inject durable liquidity into the financial system.
- RBI ने वित्तीय प्रणाली में स्थायी तरलता बढ़ाने के लिए ₹1 ट्रिलियन मूल्य के सरकारी प्रतिभूतियों की ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) खरीद और \$5 बिलियन के तीन वर्षीय डॉलर–रुपये स्वैप की घोषणा की।
- OMOs matter when the rupee is under pressure because a sharp fall in the rupee often coincides with foreign investor outflows, which drain liquidity from the banking system.
- ओएमओ महत्वपूर्ण होते हैं जब रुपया दबाव में होता है क्योंकि रुपया तेजी से गिरने पर विदेशी निवेशकों के पैसे बाहर निकलते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली से तरलता घटती है।
- OMO purchases help replenish this liquidity by injecting durable funds into banks.
- OMO खरीद से बैंक में स्थायी निधियों के जरिए यह तरलता पुनःपूर्ति होती है।

Ques: How many illegal loan lending apps were recently blocked by the Indian government?

भारतीय सरकार ने हाल ही में कितनी अवैध लोन ऐप्स को ब्लॉक किया?

- A) 87
- B) 67
- C) 45
- D) 102
- E) 120

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The government blocked 87 illegal loan lending apps after completing the required legal procedures.
- आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकार ने 87 अवैध लोन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया।
- The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) used Section 69A of the Information Technology Act, 2000, to block these apps.
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A का उपयोग किया।
- Companies running illegal online lending activities are subject to inquiries, account inspections, and investigations under the Companies Act, 2013, with legal action taken for any violations.
- अवैध ऑनलाइन लोन गतिविधियों को चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जांच, खाता निरीक्षण और जांच की जाती है, और किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
- The Ministry of Corporate Affairs is responsible for enforcing the Companies Act, 2013.
- कंपनी अधिनियम, 2013 को लागू करने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की है।

Ques: What decision was taken by the Sanjay Malhotra-headed Monetary Policy Committee (MPC) in its fifth bi-monthly meeting for FY26?

संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (JMPC) ने FY26 की अपनी पाँचवीं द्विमासिक बैठक में क्या निर्णय लिया?

- A) Increased repo rate to 6.0% / रेपो दर 6.0% की गई
- B) Reduced repo rate to 5.25% / रेपो दर 5.25% की गई

- C) Kept repo rate unchanged at 5.50% / रेपो दर 5.50% पर स्थिर रखी गई
- D) Shifted stance to 'accommodative' / रुख 'उदार' किया गया
- E) Raised CRR by 50 bps / सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI Governor Sanjay Malhotra-led Monetary Policy Committee held its 58th and fifth bi-monthly meeting for FY26 from December 3 to 5.
- आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने FY26 की पाँचवीं द्विमासिक और 58वीं बैठक 3 से 5 दिसंबर तक आयोजित की।
- The six-member MPC unanimously voted to reduce the repo rate by 25 basis points—from 5.50% to 5.25%.
- छह सदस्यीय MPC ने सर्वसम्मति से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर रेपो दर को 5.50% से घटाकर 5.25% करने का निर्णय लिया।
- The committee decided to continue with a 'neutral' monetary stance.
- समिति ने मौद्रिक रुख को 'तटस्थ' बनाए रखने का फैसला किया।

Various rates are as under with New Rate and Old Rate :

- Repo Rate : 5.25% (New rate) 5.50% (Old rate)
- Reverse Repo Rate : 3.35% (New rate) 3.35% (Old rate)
- Standing Deposit Facility (SDF) : 5.00% (New rate) 5.25% (Old rate)
- Marginal Standing Facility Rate : 5.50% (New rate) 5.75% (Old rate)
- Bank Rate : 5.50% (New rate) 5.75% (Old rate)
- Cash reserve ratio (CRR) : 3.00% (New rate) 3.50% (Old rate)
- Statutory Liquidity Ratio (SLR) : 18.00% (New rate) 18.00% (Old rate)

CPI Inflation Projections:

- For FY 2025-26 : 2%
- For Q3 FY 2025-26 : 0.6%
- For Q4 FY 2025-26 : 2.9%
- For Q1 of FY2026-27 : 3.9%
- For Q2 of FY2026-27 : 4%

GDP Growth Projections:

- For FY 2025-26 : 7.3%
- For Q3 FY 2025-26 : 7%
- For Q4 FY 2025-26 : 6.5%
- For Q1 FY 2026-27 : 6.7%
- For Q2 FY 2026-27 : 6.8%

Ques: What does the House Price Index (HPI) track in India?

भारत में हाउस प्राइस इंडेक्स (HPI) किसको ट्रैक करता है?

- A) Agricultural commodity prices / कृषि वस्तुओं की कीमतें
- B) Residential property prices / आवासीय संपत्ति की कीमतें
- C) Stock market trends / शेयर बाजार के रुझान
- D) Industrial production / औद्योगिक उत्पादन
- E) Inflation rate / मुद्रास्फीति दर

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The House Price Index (HPI), compiled quarterly by the Reserve Bank of India (RBI), tracks residential property prices using transaction-level data from registration authorities.
- हाउस प्राइस इंडेक्स (HPI), जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तिमाही आधार पर तैयार करता है, आवासीय संपत्ति की कीमतों को रजिस्ट्रेशन अधिकारियों से प्राप्त लेन के स्तर देन-है। करता ट्रैक पर आधार के डेटा
- The new base year for HPI is 2022-23, replacing the earlier 2010-11 base.
- HPI का नया बेस वर्ष 2022-23 है, जो पहले 2010-11 के बेस को बदलता है।
- In Q2 FY26, All-India HPI grew 2.2% year-on-year, led by cities like Nagpur, Ghaziabad, and Chandigarh, while quarterly trend showed a 0.6% decline due to price drops in Kolkata, Chennai, Lucknow, and Hyderabad.
- Q2 FY26 में, ऑल इंडिया-HPI वर्ष वर्ष-दर-2.2% बढ़ा, प्रमुख रूप से नागपुर, गाजियाबाद और चंडीगढ़ द्वारा बढ़ावा मिला, जबकि तिमाही रुझान में कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद में कीमतों में गिरावट के कारण 0.6% की कमी दर्ज की गई।

- HPI covers 18 major cities across India, reflecting a mix of rising and falling property prices.
- HPI भारत के 18 प्रमुख शहरों को कवर करता है, जो संपत्ति की कीमतों में वृद्धि और गिरावट दोनों को दर्शाता है।

Ques: Which Payment Bank recently received RBI's in-principle approval to convert into a Small Finance Bank, becoming the first in India to do so?

कौन सा पेमेंट बैंक हाल ही में RBI से इन में बैंक वित्त छोटे कर प्राप्त अनुमोदन प्रिंसिपल-गया बन पहला में भारत लिए के होने परिवर्तित?

- A) Paytm Payments Bank / पेटीएम पेमेंट्स बैंक
- B) Airtel Payments Bank / एयरटेल पेमेंट्स बैंक
- C) India Post Payments Bank / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- D) Fino Payments Bank / फिनो पेमेंट्स बैंक
- E) Jio Payments Bank / जियो पेमेंट्स बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) granted in-principle approval to Fino Payments Bank Limited (FPBL) to convert into a Small Finance Bank (SFB), making it the first payment bank in India to receive such approval.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (FPBL) को छोटे वित्त बैंक (SFB) में बदलने के लिए इन्दिया अनुमोदन प्रिंसिपल-, जिससे यह भारत का पहला ऐसा पेमेंट बैंक बन गया।
- FPBL was operationalized in 2017 and had applied for an SFB license in December 2023.
- FPBL का संचालन 2017 में शुरू हुआ और इसने दिसंबर 2023 में SFB लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
- With this conversion, Fino will join the list of 11 existing SFBs including AU SFB, Equitas SFB, Suryoday SFB, Utkarsh SFB, Jana SFB, Unity SFB, Capital SFB, ESAF SFB, Ujjivan SFB, Shivalik SFB, and Slice SFB.
- इस परिवर्तन के बाद, फिनो उन 11 मौजूदा SFBs में शामिल होगा जिनमें AU SFB, Equitas SFB, Suryoday SFB, Utkarsh SFB, Jana SFB, Unity SFB, Capital SFB, ESAF

SFB, Ujjivan SFB, Shivalik SFB और Slice SFB शामिल हैं।

- Eligibility: Existing payment banks controlled by residents and operating for at least 5 years can apply for conversion.
- पात्रता कम से कम और वाले नियंत्रण निवासी :5 साल से संचालित पेमेंट बैंक इस परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Requirements for SFBs:

- Maintain minimum net worth of ₹300 crore (or infuse additional capital to reach ₹300 crore within 18 months).
- Maintain a minimum Capital Adequacy Ratio of 15% of Risk Weighted Assets continuously.
- Promoters must hold at least 40% of paid-up voting equity for the first 5 years (reduce if initially above 40%).
- At least 25% of branches must be opened in unbanked rural centres.

SFB के लिए आवश्यकताएँ:

- न्यूनतम नेट वर्थ ₹300 करोड़ बनाए रखना या 18 महीने के भीतर पूंजी बढ़ाकर ₹300 करोड़ तक पहुँचाना।
- लगातार अपने जोखिम न्यूनतम का संपत्तियों भारित-15% कैपिटल अदेक्युअि अनुपात बनाए रखना।
- पहले 5 वर्षों के लिए प्रमोटर्स के पास कम से कम 40% पेड होनी इक्विटी वोटिंग अप-में प्रारंभ यदि चाहिए 40% से अधिक हो, तो इसे कम करना आवश्यक।
- कम से कम 25% शाखाएँ बिना बैंकिंग वाले ग्रामीण केंद्रों में खोलना अनिवार्य है।

About Fino Payments Bank :

- Established : 2017
- HQ : Navi Mumbai
- MD & CEO : Rishi Gupta
- Tagline : Qadar Aapki Mehnat Ki

Ques: What is the objective of the 'FPO Shakti' initiative launched by Vrutti in partnership with HSBC India?

HSBC इंडिया के साथ साझेदारी में Vrutti द्वारा लॉन्च की गई 'FPO शक्ति' पहल का उद्देश्य क्या है?

- A) Promote urban startups / शहरी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
- B) Support Farmer Producer Organisations (FPOs) with structured financing / किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को संरचित वित्तपोषण के माध्यम से समर्थन देना
- C) Provide insurance for small businesses / छोटे व्यवसायों के लिए बीमा प्रदान करना
- D) Fund renewable energy projects / नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना
- E) Develop e-commerce platforms / ईकरना विकसित प्लेटफॉर्म कॉमर्स-

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- 'FPO Shakti' is a blended, stage-based financing model designed to help Farmer Producer Organisations (FPOs) access capital and strengthen their governance, market systems, financial discipline, and digital capabilities over a 24-month structured journey.
- 'FPO शक्ति' एक मिश्रित, चरणहै मॉडल वित्तपोषण आधारित-, जो किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को पूंजी तक पहुँचने में मदद करने और 24 महीने की संरचित यात्रा के दौरान उनके शासन, बाज़ार प्रणाली, वित्तीय अनुशासन और डिजिटल क्षमता को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- The initiative is supported by HSBC India and Friends of Women's World Banking (FWWB) India, targeting 15 early-growth FPOs initially, with plans to scale to over 100 organisations.
- इस पहल को HSBC इंडिया और Friends of Women's World Banking (FWWB) इंडिया द्वारा समर्थित किया गया है, जो प्रारंभ में 15 शुरुआती विकास वाले FPOs का समर्थन करेगी, और इसे 100 से अधिक संगठनों तक विस्तार करने की योजना है।
- India has over 44,000 registered FPOs, forming one of the world's largest networks of farmer-owned collectives.
- भारत में 44,000 से अधिक पंजीकृत FPOs हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े किसान स्वामित्व-हैं। बनाते एक से में नेटवर्क सामूहिक वाले

Ques: Which organisation has received SEBI's in-principle approval to register the Raajmarg Infra Investment Trust (RIIT) as an Infrastructure Investment

Trust (InvIT)?

किस संगठन को राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT) को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के रूप में पंजीकृत करने के लिए SEBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है?

- A) NHAI / राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
- B) PGCIL / पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
- C) NTPC / एनटीपीसी
- D) IRCON / इरकॉन
- E) GAIL / गेल

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The National Highways Authority of India (NHAI) received in-principle approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to register the Raajmarg Infra Investment Trust (RIIT) as an Infrastructure Investment Trust (InvIT).
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT) को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के रूप में पंजीकृत करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी।
- This approval was granted under the SEBI (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014.
- यह मंजूरी SEBI (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (विनियम, 2014 के तहत दी गई है।
- To receive the final approval, RIIT must fulfil several conditions over the next 6 months, including appointment of directors, submission of financial statements, and compliance with regulatory norms.
- अंतिम मंजूरी प्राप्त करने के लिए, RIIT को अगले 6 महीनों में कई शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे निदेशकों की नियुक्ति, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना और नियामक नियमों का पालन करना।
- In November 2025, NHAI incorporated Raajmarg Infra Investment Managers Pvt. Ltd. (RIIMPL) as the Investment Manager for RIIT.
- नवंबर 2025 में, NHAI ने राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (RIIMPL) को RIIT के निवेश प्रबंधक के रूप में शामिल किया।
- RIIMPL has been established as a collaborative venture with equity participation from major banks and financial institutions such as SBI, PNB, NaBFID, Axis Bank, Bajaj Finserv Ventures Ltd., HDFC Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, IndusInd Bank, and Yes Bank.

• RIIMPL को प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसे SBI, PNB, NaBFID, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व वेंचर्स लिमिटेड, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक की इक्विटी भागीदारी के साथ एक सहयोगी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है।

Ques: Which organisation invested USD 50 million in GFCL EV Products Limited to help set up India's first fully integrated battery materials manufacturing facility?

किस संगठन ने भारत की पहली पूर्णतः एकीकृत बैटरी सामग्री विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए GFCL EV प्रोडक्ट्स लिमिटेड में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया?

- A) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक
- B) World Bank / विश्व बैंक
- C) International Finance Corporation (IFC) / अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) KfW Development Bank / KfW विकास बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The International Finance Corporation (IFC) invested USD 50 million (approximately Rs 450 crore) in GFCL EV Products Limited through compulsorily convertible instruments.
- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम) IFC) ने अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय साधनों के माध्यम से GFCL EV प्रोडक्ट्स लिमिटेड में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) लगभग 450 करोड़ रुपये (का निवेश किया।
- The investment aims to establish India's first fully integrated battery materials manufacturing facility.
- यह निवेश भारत की पहली पूर्णतः एकीकृत बैटरी सामग्री विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है।
- The greenfield facility will focus on large-scale production of Lithium Hexafluorophosphate, electrolyte formulations, Lithium Iron Phosphate (LFP) cathode materials, and PVDF/PTFE binders used in electric vehicles and energy storage systems.
- यह ग्रीनफील्ड सुविधा लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट, इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म्युलेशन, लिथियम

आयरन फॉस्फेट कैथोड सामग्री और पीवीडीएफ/पीटीएफई बाइंडर्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर केंद्रित होगी, जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में उपयोग किया जाता है।

- Barclays served as the financial advisor to GFCL EV for this transaction.
- इस लेनदेन के लिए बार्कलेज ने GFCL EV के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया।

About International Finance Corporation :

- Established : 1956
- HQ : Washington, D.C., United States
- Managing Director : Makhtar Diop

Ques: According to RBI guidelines, customer communication by Scheduled Commercial Banks (SCBs) must be provided in how many and which languages?

RBI दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा ग्राहक संचार कितनी और किन भाषाओं में प्रदान किया जाना चाहिए?

- A) Two – English and Hindi / दो – अंग्रेज़ी और हिंदी
B) Two – Regional language and English / दो – क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेज़ी
C) Three – Hindi, English, and Regional language / तीन – हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषा
D) Four – Hindi, English, Sanskrit, and Regional language / चार – हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा
E) One – Only Regional language / एक – केवल क्षेत्रीय भाषा

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI guidelines mandate that all customer communication by Scheduled Commercial Banks (SCBs) must be trilingual: Hindi, English, and the regional language.
- RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को ग्राहक संचार तीन भाषाओं में प्रदान करना अनिवार्य है : हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषा।

- Banks must adopt a Board-approved policy for branch management, ensuring customer-friendly services.
- बैंकों को शाखा प्रबंधन के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीति अपनानी होती है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
- Banks must display indicator boards, provide service booklets, and ensure that forms, pay-in slips, and passbooks are available in Hindi, English, and the regional language.
- बैंकों को संकेतक बोर्ड प्रदर्शित करने, सेवा पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने और सभी फॉर्म, पे-इन स्लिप्स, पासबुक आदि हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- DFS instructed Public Sector Banks (PSBs) to strictly follow these regional language guidelines.
- DFS ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को इन क्षेत्रीय भाषा दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
- Indian Banks' Association (IBA) advised PSBs to recruit Local Bank Officers (LBOs) to improve communication with customers, especially in rural and semi-urban areas.
- इंडियन बैंक्स' एसोसिएशन (IBA) ने PSBs को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों से बेहतर संवाद के लिए स्थानीय बैंक अधिकारियों (LBOs) की भर्ती करने की सलाह दी है।
- Customer Service Associates (CSAs) must pass a Local Language Proficiency Test (LPT) for the posting location.
- ग्राहक सेवा सहयोगियों (CSAs) को अपने कार्यस्थल की स्थानीय भाषा में दक्षता परीक्षा (LPT) उत्तीर्ण करनी होती है।
- Aim: seamless communication in regional languages and improved customer experience.
- उद्देश्य :क्षेत्रीय भाषाओं में सुगम संचार और बेहतर ग्राहक सेवा।

Ques: Which bank has launched the premium 'Luxura' card powered by RuPay?

किस बैंक ने रूपे द्वारा संचालित प्रीमियम 'लक्जूरा' कार्ड लॉन्च किया है?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- E) Canara Bank / केनरा बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Punjab National Bank (PNB) has launched a premium card named 'Luxura', powered by RuPay.
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने रूपे द्वारा संचालित एक प्रीमियम कार्ड 'लक्जुरा' लॉन्च किया है।
- The card is available for individuals aged between 21 and 70 years.
- यह कार्ड 21 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
- For salaried persons, the income eligibility is ₹2.5 lakh per month and above.
- वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आय मानदंड प्रति माह ₹2.5 लाख या उससे अधिक है।
- For non-salaried individuals, the applicant must have a minimum annual income of ₹30 lakh.
- गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय ₹30 लाख होनी चाहिए।

About Punjab National Bank :

- Established : 19 May 1894
- HQ : New Delhi
- MD & CEO : Ashok Chandra
- Tagline : The Name You Can Bank Upon

Ques: What is the primary aim of SEBI's newly launched Past Risk and Return Verification Agency (PaRRVA)?

SEBI द्वारा शुरू की गई Past Risk and Return Verification Agency (PaRRVA) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) To regulate mutual fund NAV calculations / म्यूचुअल फंड NAV गणना को नियंत्रित करना
- B) To prevent misleading claims about past performance in financial product advertisements / वित्तीय उत्पादों के विज्ञापनों में पिछले प्रदर्शन से जुड़े भ्रामक दावों को रोकना
- C) To monitor insider trading cases / इनसाइडर ट्रेडिंग मामलों की निगरानी करना
- D) To create a central registry for investment advisors / निवेश सलाहकारों के लिए

केंद्रीय रजिस्ट्री बनाना

E) To certify financial influencers / वित्तीय इन्फ्लुएंसर्स को प्रमाणित करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) launched the Past Risk and Return Verification Agency (PaRRVA) to prevent misleading claims related to past performance made by Research Analysts, Investment Advisors, and stock brokers in financial product advertisements.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Past Risk and Return Verification Agency (PaRRVA) की शुरुआत की ताकि वित्तीय उत्पादों के विज्ञापनों में रिसर्च एनालिस्ट, निवेश सलाहकार और स्टॉक ब्रोकरों द्वारा किए जाने वाले पिछले प्रदर्शन से जुड़े भ्रामक दावों को रोका जा सके।
- This is the world's first initiative of its kind, launched in partnership with the National Stock Exchange (NSE) and CARE Edge Ratings.
- यह विश्व का पहला ऐसा प्रयास है, जिसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और CARE Edge Ratings के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है।
- Intermediaries submit data through secure API or file upload, which is validated by the PaRRVA–NSE Data Centre (PDC). The system generates 50+ risk–return metrics with T+1 portfolio checks.
- मध्यस्थ सुरक्षित API या फ़ाइल अपलोड के माध्यम से जानकारी जमा करते हैं, जिसे PaRRVA–NSE डेटा सेंटर (PDC) द्वारा सत्यापित किया जाता है। यह प्रणाली T+1 पोर्टफोलियो जांच के साथ 50 से अधिक जोखिम–प्रतिफल मीट्रिक तैयार करती है।
- Earlier, SEBI's rules restricted registered intermediaries from showing their past performance, even if legitimate, while unregistered players freely advertised unverifiable returns — creating a regulatory imbalance.
- पहले, SEBI के नियम पंजीकृत मध्यस्थों को अपने पिछले प्रदर्शन दिखाने से रोकते थे, जबकि गैर-पंजीकृत खिलाड़ी अप्रमाणित रिटर्न का प्रचार कर निवेशकों को आकर्षित करते थे, जिससे नियामकीय असंतुलन पैदा होता था।
- PaRRVA was initially announced in December 2024 during SEBI's 208th Board Meeting and the operational framework was officially issued in April 2025.
- PaRRVA की घोषणा पहली बार दिसंबर 2024 में SEBI की 208वीं बोर्ड बैठक में की गई थी, और इसका परिचालन ढांचा अप्रैल 2025 में जारी किया गया।
- As per SEBI's circular, a Credit Rating Agency (CRA) with at least 15 years of experience, ₹100 crore net worth, grievance redressal mechanisms (including

ODR), and 250+ rated issuers can act as PaRRVA.

- SEBI के परिपत्र के अनुसार, 15 वर्षों का अनुभव, ₹100 करोड़ की शुद्ध संपत्ति, शिकायत निवारण तंत्र) ODR सहित(, और 250+ रेटेड इश्यूअर्स वाले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) CRA) को PaRRVA के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
- A recognised Stock Exchange with at least 15 years of experience, ₹200 crore net worth, nationwide terminals, and grievance redressal mechanisms (including ODR) can act as PaRRVA Data Centre (PDC).
- कम से कम 15 वर्षों के अनुभव, ₹200 करोड़ की शुद्ध संपत्ति, देशभर में टर्मिनल, और शिकायत निवारण तंत्र) ODR सहित (वाली मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को PaRRVA डेटा सेंटर) PDC) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

